



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला सोमवार, 18 जनवरी, 2010/28 पौष, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जनवरी, 2010

सं पब ए (3)15/99.— हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयागे के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में नाट्य कला निरीक्षक (वर्ग—III अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग नाट्य कला निरीक्षक (वर्ग—III अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010, है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: पीयूबी-ए (3)10/87 तारीख 1-03-1989 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग नाट्य कला निरीक्षक, वर्ग-3 सेवाए भर्ती और प्रोन्नति और सेवा की कतिपय शर्तें नियम, 1989 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उपनियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव ।

उपाबन्ध—“क”

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश में नाट्य कला निरीक्षक, वर्ग—III, (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.— नाट्य कला निरीक्षक
2. पदों की संख्या.— 9 (नौ)
3. वर्गीकरण.— वर्ग—III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.—4400—150—5000—160—5800—200—7000 रुपये ।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—6600 /— रुपये प्रतिमास (वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महगाई वेतन के बराबर)

5. चयन पद अथवा अचयन पद.— अचयन ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.— 18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में तज अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है ।

परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं—(क) अनिवार्य अर्हताएं—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से दसवीं पास या इसके समकक्ष।

(ii) सरकारी/अर्धसरकारी/रजिस्ट्रीकृत सांस्कृतिक संगठनों के अधीन नाट्य निर्देशन/नाट्य प्रस्तुत करने और सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालित करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

(ख) वांछनीय अर्हताएं—(i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

(ii) राज्य के साहित्य और कला का अच्छा ज्ञान हो।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं—आयु—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं—लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता—(i) यथास्थिति, पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या-15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सेकेण्डमेंट आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा—अभिनेता(ओं)/कलाकार(रों)/हारमोनियम मास्टर(रों)/स्टेज मास्टर(रां) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका अपने-अपने ग्रेड में 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में समरूप वेतनमान में कार्यरत और उपर्युक्त स्तम्भ संख्या: 7 के सामने सीधी भर्ती के लिए यथा-विहित शैक्षिक अर्हताए रखने वाले इस पद के पदधारियों में से सेकेण्डमेंट आधार पर:

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों की उनके सेवाकाल के आधार पर पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरीयता सूची तैयार की जाएगी।

परन्तु यह और कि प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में चक (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अधीन कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे भी कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्होंने जनजातीय क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है ऐसे क्षेत्र से उसके अपने संवर्ग (कांडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जन-जातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों के तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.— उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जन जातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।
6. जिला कांगडा के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. उप तहसील कमरु के काठवाड और कोरगा पटवारवृत, सिरमौर जिला में रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगडा पटवार वृत, बाली-चौकी उप-तहसील के गाडा-गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पधर-तहसील के झाखाड, कटूगढ, ग्रामन, देवगढ, सरैला, रोपा, कथोग, सिल्ह भडवानी, हस्तपुर, घमरेकड और भटेठ पटवार वृत, थुनाग तहसील के चियुणी कालीपर, मानगढ, थाच-बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिण मंगरू पटवार वृत और सुन्दर नगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवाएँ यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवा काल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवाएँ जो भी कम होएँगी।

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदाधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोब्लाइज्ड आर्मड फोरसिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्निकल सर्विसिज) रूलज 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवाएँ यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उस के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.— जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.— किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारतीय होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाए :—

(1) **संकल्पना.**—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में नाट्य कला निरीक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.**—निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्षता को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियाँ.**—संविदा के आधार पर नियुक्त नाट्य कला निरीक्षक को 6600/—रुपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चात्तवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 150/—रुपये (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) **नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.**—निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) **चयन प्रक्रिया.**—संविदा नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिये चयन समिति.**—जैसी सम्बू भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) **करार.**—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—“ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) **निबन्धन और शर्तें.**—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6600/—रुपये की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 150/— रुपए वार्षिक (पद के वेतनमान के प्रारम्भिक न्यूनतम आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहवद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा, पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिये भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिये पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे कि एफ0 आर0—एस0आर0, छुटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम और आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. **आरक्षण.—** सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा.—** लागू नहीं।

18. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—ख

नाट्य कला निरीक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमतिपुत्र/पुत्रीनिवासी.....
.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, की मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने नाट्य कला निरीक्षक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार नाट्य कला निरीक्षक के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझी जामगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकमरुपए प्रति माह होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त नाट्य कला निरीक्षक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त नाट्य कला निरीक्षक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त नाट्य कला निरीक्षक कर्तव्य (ड्युटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना आपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ/जी0पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1.-----

(नाम व पूरा पता)

2.-----

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1.-----

(नाम व पूरा पता)

2.-----

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No. Pub-A (3)15/99 dated 8 -01-2010 as required under clause(3) of Article 348 of Constitution of India].

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMEN

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8th January, 2010

No. Pub. A(3)15/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post

of Drama Inspector (Class-III Non-Gazetted) in the Department of Information & Public Relations Himachal Pradesh, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Information and Public Relations, Drama Inspector (Class-III Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Public Relations Department Drama Inspector (Class-III Non-Gazetted) Services Recruitment and Promotion and certain conditions of the services rule 1989 notified vide this Department Notification No.Pub-A(3)10/87 dated 01-03-1989 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made under these rules.

By order,
Sd/-
Secretary.

Annexure-"A"

Recruitment and Promotion Rules for the post of Drama Inspector, Class-III (Non-Gazetted) in the Deptt. of Information & Public Relations, H. P.

- 1. Name of the Post.**—Drama Inspector
- 2. Number of Post.**—9 (Nine)
- 3. Classification.**—Class-III (Non-Gazetted)
- 4. Scale of Pay.**—(i) *Pay Scale for regular incumbents.*—Rs. 4400-150-5000-160-5800-200-7000.
(ii) *Emoluments for Contract employees.*—Rs. 6600/- per month (which shall be equal to initial of pay scale + Dearness pay).
- 5. Whether Selection Post or non-selection Post.**— Non Selection.
- 6. Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations /Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servant . This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifcations required for direct recruits.—

(a) *Essential Qualifications.*—(i) Matric or its equivalent from a recognized University/Board.

(ii) At least 3 years experience in directing/producing drama and conducting dramatic/ Cultural performance under Government/Semi-Government/Registered Cultural Organizations.

(b) *Desirable qualifications.*—(i) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

(ii) Good knowledge of literature and art of the State.

8. Whether age and educational qualificaions prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotees.—*Age.*—Not applicable.

Educational Qualification.—Not applicable.

9. Period of probation if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 50% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column No. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

(ii) 50% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Actor(s)/ Artist(s)/Harmonium Master(s)/Stage Master(s) with at least 5 years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any in the respective grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale and possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruitment against Column No. 7 above from other Departments of the H. P. Government/Centrtal Government.

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of their length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prepared.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult area subject to adequate number of posts available in such area;

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that the Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso supra the “term” in Tribal / Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such area keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso supra the Tribal/Difficult Area shall be as under.—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayatys of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pub Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrebar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration,

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotions Rules for the post, whichever is less,

Provided further that where a person become ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of Seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the HP.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by the direct recruitment.—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the H.P. Public Service Commission or other recruiting authority, the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc, of which will be determined by the H. P. Public Service Commission other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms & conditions given below:

(I) Concept.—(a) Under this policy, the Drama Inspector in the Department of Information & Public Relations H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.**—The Director Information & Public Relations H. P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Services Selection Board Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) Contractual Emoluments.—The Drama Inspector appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 6600/- per month (which shall be equal to initial of pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. 150/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) Appointing /Disciplinary Authority.—The Director, Information & Public Relations H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) Selection Process—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. subordinate services Selection Board.

(V) Committee for Selection of contractual appointments—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H. P. Subordinate Services Selection Board from time to time.

(VI) Agreement.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these Rules.

(VII) Terms & conditions.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs 6600/- per month (which shall be equal to initial of pay scale +Dearness pay). The Contract appointee will be entitled for annual increase in contractual amount @ Rs. 150/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given .

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provision of service rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination.— Where the state Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

18. Power to relax.—Not Applicable.

Annexure-“B”

Form of contract/agreement to be executed between Drama Inspector and the Government of Himachal Pradesh through Director, Information & Public Relations, H. P. This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ between Sh./Smt. _____ s/o/D/o Sh. _____ R/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director, I&PR Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Drama Inspector, on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Drama Inspector, for a period of 1 year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e on _____. And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. _____ per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Drama Inspector, will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Drama Inspector. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A Contractual Drama Inspector, will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond

12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

9. The employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES

1. _____

(Name and full address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESSES

1. _____

(Name and full address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 जनवरी, 2010

संख्या सिंचाई 11-19/2009-शिमला.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव बागड़ा, तहसील ठियोग, जिला शिमला में उठाऊ पेयजल योजना गिरि खड्ड से शिमला शहर के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला, को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला, को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि का रेखांक समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र/हैटरों में
शिमला	ठियोग	बागड़ा	3/2/3/1	0-04-34
			3/2/3/4	0-00-12
			3/2/3/5	0-01-20
			31/1	0-00-28
			36/1	0-00-12
			35/1	0-00-20
			किता-6	0-06-26 है०

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 18 जनवरी, 2010

सं०पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ०—(5)104/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कुन्नू/582, तहसील पधर, जिला मण्डी मे कुन्न-बडीधार वाया गजौन सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी, के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा)
मण्डी	पधर	कुन्नु/582	374/288/1	0-10-13
		कुल जोड़	किता- 1	0-10-13

शिमला-2, 18 जनवरी, 2010

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0-(5)146/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव डडोह, तहसील चच्योट, जिला मण्डी में गोहर कांढा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी, के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा)
मण्डी	चच्योट	डोह	760/1	0-10-9
		कुल जोड़	किता- 1	0-10-9

शिमला-2 18 जनवरी, 2010

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0) एफ0-(5) 32/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव ठोडो, तहसील व जिला सोलन में सोलन-मिनस सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
सोलन	सोलन	ठोडो	1203/1	40-00
		कुल जोड़	किता-1	40-00

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

श्रम एवं रोजगार विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 16 जनवरी, 2010

संख्या श्रम (बी) 1-3/2007(स्थापना) एल0आई0.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2(बी) 7-4/92-श्रम तारीख 04-11-1997 तथा दिनांक 4-05-2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग, श्रम निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, श्रम एवं रोजगार विभाग, श्रम निरीक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध—“अ” का.—हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग, श्रम निरीक्षक, संशोधन.—वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध—“अ” में,—

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
“33 (तैंतीस)”

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान :

13900/—रुपए (10300/— रुपए जमा 3600/— रुपए ग्रेड पे) प्रतिमास।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :

स्तम्भ 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 13,900/— रुपए” ।

(ग) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

(ii) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।”

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा;

(घ) स्तम्भ संख्या 15, के पश्चात् निम्नलिखित स्तम्भ 15—क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“15—क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—संविदा नियुक्ति, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी:—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग में श्रम निरीक्षक को, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.—श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धिया.—संविदा के आधार पर नियुक्त श्रम निरीक्षक को 13,900/— रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13,900/— रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे अर्थात् 10300/— रुपए जमा 3600/— रुपए के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थिका किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।"

आदेश द्वारा,
अनिल खाची,
सचिव।

उपाबन्ध—“ख”

श्रम निरीक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य श्रमायुक्त एवं निदेशक, श्रम एवं रोजगार, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य श्रमायुक्त एवं निदेशक, श्रम एवं रोजगार, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने श्रम निरीक्षक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार श्रम निरीक्षक के रूप में..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13,900/— रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त श्रम निरीक्षक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त श्रम निरीक्षक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमादन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त श्रम निरीक्षक कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनपु युक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (B)1-3/2007(Estt.) L.I., dated 16-01-2010 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th January, 2010

No. Shram(B)1-3/2007(Estt.)L.I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Labour & Employment Department, Labour Inspector, Class-III

(Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services) Recruitment & Promotion Rules, 1997 notified *vide* this department notification 2(B)7-4/92-Shram, dated 4-11-1997 and dated 4-05-2002 namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Labour & Employment Department, Labour Inspector, Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services) Recruitment & Promotion (Second amendment) Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-“A” .—In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Labour & Employment Department Inspector, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(a) For the existing provisions against Col. No. 2 the following shall be substituted, namely.—“33 (Thirty three)” ;

(b) For the existing provisions against Col. No. 4 the following shall be substituted, namely:—

(i) Pay Scale for regular incumbents Rs. 13900/- P.M. (Rs.10300+3600 as Grade Pay).

(ii) Emoluments for Contract employees Rs.13900/- as per details given in **Col. 15-A**.

(c) For the existing provision against Col. No.10 the following shall be substituted, namely.—“(i) 25% by direct recruitment or on contract basis.

(ii) 75% by promotion failing which by direct recruitment”.

The contract employees will get emoluments as given in **Col. 15-A** and will be governed by service conditions as specified in the said column,” After Col. No. 15, the following Col.15-A shall be inserted, namely:—

“15-A (Selection for appointment to the post by Contract Appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(1) **CONCEPT.**—(a) Under this policy Labour Inspector in the Department of Labour and Employment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extended on year to year basis.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC/HP SSB.**—The Labour Commissioner, Himachal Pradesh. After obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Labour Inspector appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 13900/- P.M. (which shall be equal to minimum of Pay Band +Grade Pay).

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Labour Commissioner, Himachal Pradesh shall be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vivavoce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which shall be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these Rules.

TERMS AND CONDITIONS

(a) The contractual appointee shall be paid fixed contractual amount @ Rs 13900/-P.M. (which shall be equal to minimum of Pay Band +Grade Pay Viz. Rs. 10300+3600).

(b) The service of the Contract Appointee shall be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee shall be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave shall be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate shall have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR,SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.”

By order,
ANIL KHACHI,
Secretary.

Form of contract/ agreement to be executed between the Labour Inspector (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through Labour Commissioner-cum-Director of Employment, H.P. (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....
Between.....Sh/Smt.....S/o/D/oShri.....R/o.....
.....Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Labour Commissioner-cum-Director of Employment, Himachal Pradesh (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Labour Inspector (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Labour Inspector (Name of the post) for a period of one year commencing on day ofand ending on the day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on.....and information notice shall not be necessary.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.13900/- P.M.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Labour Inspector will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any kind is admissible to the contractual Labour Inspector (Name of the post). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rule.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. First Party will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of First Party will not be permitted from one place to another in any case.

7. First Party shall submit a certificate of his/ her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. First Party shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF shall not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS WHEREOF the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

.....

.....

(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.

.....

.....

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

.....

.....

(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.

.....

.....

(Name and full Address)

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 16th January, 2010

No. Shram (B) 3-1/ 2006 (Estt.) L.O.—The Governor, Himachal Pradesh on the recommendations of the Departmental Promotion Committee is pleased to order the promotion of Sh. Raj Kumar, Labour Inspector to the post of Labour Officer, (Class-II, Gazetted) in the pay scale of Rs. 7000-10980 (Pre-Revised), in the Labour and Employment Department, Himachal Pradesh, on regular basis in pursuance of Deptt. of Personnel instruction's issued vide letter No. PER(AP)-C-F(1)-1/2009, dated 16th November, 2009, in the public interest.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post him as Labour Officer at Chamba against Sh. Rajesh Panghania, Labour Officer. Further Sh. Panghania, Labour Officer, Chamba is hereby transferred and posted at Una against vacancy.

3. Sh. Raj Kumar, on his promotion, shall remain on probation for a period of two years in the first instance. He shall be entitled to exercise for fixation of pay under the provisions of F.R. 22(1)(a)(i) within one month from the date of receipt of this order.

4. Sh. Raj Kumar is directed to report for duty at his new place of posting within a fortnight positively. The promotion shall take place on joining at new place of posting. No extension in joining period will be allowed in any case.

By order,
ANIL KHACHI,
Secretary.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जनवरी, 2009

संख्या एफ0डी0एस0ए0(3)-3/90-1.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत का राजपत्र, असाधारण, तारीख 18-12-2009 में प्रकाशित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) मन्त्रालय के एस0 ओ0 संख्या 3249 (ई) तारीख 18-12-2009 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ट्रेड आटिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आटिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1).—इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आटिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) अमेंडमेंट आर्डर, 2010 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा और यह 30-09-2010 तक या इस निमित्त भारत सरकार द्वारा जारी किसी आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रवृत्त रहेगा ।

2. शडयूल-1 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश ट्रेड आटिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 में भाग-ई अदर आटिकलज (अन्य वस्तुएं) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थात्:—

“शूगर” (चीनी) ।

आदेश द्वारा,
अनिल खाची,
सचिव ।

[Authoritative English text of this Department Notification No, FDS-A(3)3/90-I dated 16th January, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, 16th January, 2010

No. FDS-A (3)3/90-I.—In exercise of powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, read with S.O. No. 3249 (E) dated 18th December, 2009 Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) Government of India published in the extra ordinary Gazette of India dated 18th December, 2009, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following order further to amend the SCHEDULE-I appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing & Control) Order, 1981, namely:—

1. Short titled and Commencement.—(1) This order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2010.

(2) It shall come into force at once and shall remain in force up to 30-09-2010 or till any order issued by the Government of India in this behalf whichever is earlier.

2. Amendment of SCHEDULE-I.—In Schedule-1 appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981 under Part-E (Other articles) the following item shall be added namely:—

“Sugar”

By order,
ANIL KHACHI,
Secretary.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जनवरी, 2010

संख्या एफ0डी0एस0ए0(3)—7/91-11.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 का (केन्द्रीय अधिनियम, संख्याक 54) की धारा 72 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एफ0डी0एस0-ए(3)—7/91 तारीख 29-10-2004 द्वारा जारी और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 01-12-2004 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम बनाने का प्रस्ताव करती है और उन्हें एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार जनसाधारण के सूचनार्थ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर इनके पूर्व प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की अवधि के अवसान के पश्चात विचार किया जायेगा ।

इन प्रारूप नियमों से संभावित: प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति, यदि, इन नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है तो वह उपरोक्त नियत अवधि के भीतर उसे/उन्हें सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले,) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा, उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई है/हों, पर राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) तीय संशोधन, नियम, 2009 है ।

2. अनुसूची-9 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 2004 की अनुसूची-9 में मद 21 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

“22 मोटरयानों के लिए एल0पी0जी0 डिस्पेंसर के सत्यापन के लिए फीस 1000 रुपये”

आदेश द्वारा,
अनिल खाची,
सचिव ।

[Authoritative English text of this Department Notification No, FDS-A(3)7/91-Part-II dated 18-1-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 18th January, 2010

No. FDS-A (3)7/91-II.—In exercise of powers conferred by section 72 of Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985 (Central Act No. 54 of 1985) the Governor, Himachal Pradesh in consultation with Government of India proposes to make the following draft rules further to amend the Himachal Pradesh Standards of Weight and Measures (Enforcement) Rules 2004 issued vide Government notification No. FDS-A(3)-7/91, dated 29-10-2004 and published in Rajpatra (Extra Ordinary) dated 01-12-004, are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh as required under sub section (1) of Section 72 of the said Act for information of the general public and a notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the State Government after the expiry of a period of 30 days from the date of their previous publication;

If any person likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) to make in respect of these rules, he may send the same to the Secretary (FCS&CA) to the Government of Himachal Pradesh within the above stipulated period; Objection(s) or suggestion(s), if any, received within above stipulated period shall be taken into consideration by State Government before finalization of the said rules, namely:—

1. Short titled.—These rules may be called the Himachal Pradesh Standards of Weights and Measures (Enforcement) Third Amendment Rules, 2009.

2. Amendment of Schedule-IX.—In the Himachal Pradesh Standards of Weights and Measures (Enforcement) Rules, 2004, in schedule IX, after item 21, the following shall be added namely:—

“22 fee for verification of LPG Dispenser for Motor Vehicles Rs. 1,000/- ”

By order,
ANIL KHACHI,
Secretary.